

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-9
संख्या- 843/XXVII(9)/2010/स्टाम्प-42/2008
देहरादून: दिनांक: 16 नवम्बर, 2010

कार्यालय-ज्ञाप

भारत सरकार कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 19.09.2009 से ई-स्टाम्पिंग व्यवस्था लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत होने वाले कतिपय विलेखों के पंजीकरण में स्टाम्प शुल्क की धनराशि प्राप्त होती है, जिन्हे रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज उत्तराखण्ड कानपुर (यू0पी0) द्वारा राज्य में पंजीकृत होने वाले कम्पनियों से वसूल किया जाना है।

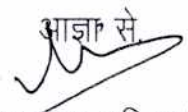
स्टाम्प शुल्क की इस धनराशि को उत्तराखण्ड सरकार के खाते में हस्तान्तरित किया जाता है। भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या HQ/7/2002/कम्प्यूटरीकरण दिनांक 12.08.2010 में प्राप्त निदेशों के अनुपालन में MCA 21 द्वारा भुगतान किये गये Unutilized/excess स्टाम्प ड्यूटी रिफण्ड से सम्बन्धित सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु श्री एल0 एन0 पन्त बजट अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन जिनका फोन नं0- 9412155749 email id- Pant-in@yahoo.co.in, Pant-in@rediffmail.com है, को नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

/
(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या-843 (1)/XXVII(9)/2010/स्टाम्प-42/2008 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कमरा नं0-507 "ए" विंग शास्त्रीभवन, डा0 राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त उत्तराखण्ड।
- 3- समस्त जिलाधिकारी/जिला निबन्धक, उत्तराखण्ड।
- 4- महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- श्री एल0 एन0 पन्त बजट अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
- 7- गार्ड फाइल।


(एस0एस0 वल्दिया)
उप सचिव।